<u>आकाशवाणी गोरखपुर</u>
<u>प्रादेशिक समाचार</u>

<u>दिनांक–**18 अप्रैल** 2026</u> **7:20 AM**

पहले मुख्य समाचार।

1. दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने से लोकसभा में पारित नहीं हो सके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से जुड़े तीनों विधेयक।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा– संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है।
3. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार को मामले की जांच कराने की सौंपी ज़िम्मेदारी।
4. प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिये लागू की न्यूनतम मजदूरी। अब गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के कुशल श्रमिकों को प्रति माह तीन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये और बाकी जिलों के श्रमिकों को तेरह सौ पैंतीस रूपये ज्यादा मिलेंगे।

****

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में दो हजार उन्तीस के चुनाव से ही महिलाओं को तैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने के लिये सरकार द्वारा लाये गये नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक यानी एक सौ इकतीसवां संविधान–संशोधन विधेयक– दो हजार छब्बीस, सहित तीनों विधेयक लोकसभा में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सके। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पक्ष में दो सौ अट्ठानबे और विपक्ष में दो सौ तीस मत पड़े। इस विधेयक के पारित न होने के कारण परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून–संशोधन विधेयक, 2026 को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया। लोकसभा की बैठक आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग–अलग सोशल मीडिया पोस्ट में आश्वस्त किया कि सरकार ये अधिनियम लागू करने के लिये कटिबद्ध है। श्री मोदी ने अपने एक पोस्ट में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम इस भ्रम में न रहें कि देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। ये उसका हक है, जिसे दशकों से रोका गया है।

विधेयक पारित न होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन न करके ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का गुस्सा झेलेगी।

इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगत वितरण होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।

परिसीमन के प्रावधान से ही एससी और एसटी जिसकी संख्या बढती है उसकी सीटें भी बढने का प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं, वह एससी और एसटी सीटों का बढोत्तरी का विरोध कर रहा है।

श्री शाह ने कहा कि इस परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटों में वृद्धि का प्रावधान है।

कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, तामिलनाडु और केरल की अभी स्ट्रेंथ है 129, 23. 76 प्रतिशत अब 50 टका वृद्धि कर, कर जब ये पांचों राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं। 129 से बढ़कर सीटें 195वें होगीं इसका 816 में प्रतिशत 23. 87 आये।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना–देना नहीं है।

सच तो यह है कि यह कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है। इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना–देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक है, जिसे इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया गया था। यह विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राजनाथ ने राहुल गांधी के भाषण से ऐसी टिप्पणियां हटाने को कहा।

इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग नेताप्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे बार–बार मैजीशियन कह कर। देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया इन्हें तुरंत कार्यवाही के बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगना चाहिए।

****

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज करने और आरोप की जांच कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया

कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करें या जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दें। यह निर्देश भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की एक याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ की एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

****

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। नई दरों को बीते एक अप्रैल से लागू करने सम्बन्धी अधिसूचना कल जारी कर दी गयी। एक रिपोर्ट–

नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी के लिये अलग–अलग मजदूरी दरें तय की गयी हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को श्रेणी एक में रखा गया है। अन्य नगर निगमों वाले जिले श्रेणी दो में हैं जबकि बाकी सभी जिले श्रेणी तीन में शामिल किये गये हैं। अब गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के कुशल श्रमिकों को मार्च की तुलना में तीन हजार दो सौ अट्ठासी रूपये प्रतिमाह ज्यादा मिलेंगे। प्रदेश के अन्य नगर निगमों व जिलों में कार्यरत श्रमिकों की भी मजदूरी कम से कम तेरह सौ पैंतीस रूपये बढ़ेगी। सरकार ने नई मजदूरी दरों को अंतरिम राहत के रूप में लागू करने का फैसला किया है। इन्हें जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा। समाचार कक्ष से अरूण।

उधर, गौतमबुद्धनगर में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले चौबीस कारखानों से जुड़े दो सौ तीन संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त करने, धनराशि की वसूली करने और सम्बन्धित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

****

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि होर्मुज जल–डमरू–मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराघची ने कहा कि इस्राएल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के अनुरूप जल–डमरू–मध्य पूरी तरह से खोल दिया गया है। उधर, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि ईरान ने होर्मुज जल–डमरू–मध्य को पूर्ण आवागमन के लिए खोल दिया है। इस घोषणा के बाद तेल के मूल्यों में ग्यारह प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

उधर केन्द्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देशभर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में कल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक पांच किलो वाले 16 लाख 50 हजार से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान से दो हजार 361 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है।

****

दुग्ध विकास और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ में दो दिवसीय दुग्ध स्वर्ण महोत्सव–2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव में डेयरी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विण्डो व्यवस्था के माध्यम से इच्छुक निवेशकों के साथ लगभग 5 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू भी किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आज डेयरी क्षेत्र प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है, बल्कि राज्य के सकल मूल्यवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 10 हजार पशुपालक, दुग्ध उत्पादक और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं।

****

प्रदेश भर में आठवें पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बताया कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, गर्भस्थ शिशु और नवजात बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं।

****